भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं0-203
उत्तर देने की तारीख 06 दिसम्बर, 2013

बी.एस.एन.एल. तथा एम.टी.एन.एल. की वित्तीय स्थिति

203. श्री के.एन.बालगोपाल :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले पांच वर्षों में बी.एस.एन.एल. तथा एम.टी.एन.एल. की वित्तीय स्थिति बदतर हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास एम.टी.एन.एल. तथा बी.एस.एन.एल. हेतु कोई पुनरूद्धार पैकेज है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. (श्रीमती) किल्ली क्रुपारानी)

(क) और (ख) : भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने वर्ष 2009-10 से हानियां उठाई हैं। बीएसएनएल और एमटीएनएल के खातों के लेखा परीक्षित विवरण के अनुसार उनके द्वारा अर्जित लाभों/उठाई गई हानियों का विवरण निम्नानुसार है:-

(करोड़ रूपए में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
बीएसएनएल	(+)575	(-)1823	(-)6384	(-)8851	(-)7884
एमटीएनएल	(+)211	(-)2611	(-)2802	(-)4110	(-)5321

बीएसएनएल और एमटीएनएल की बढ़ती हानियों के प्रमुख कारण राजस्व में तीव्र कमी और व्यय में वृद्धि हैं। राजस्व में होने वाली कमी के कारण निम्नानुसार हैं:-

- फिक्स वायरलाइन के स्थान पर मोबाइल वायरलैस का प्रयोग।
- मोबाइल वायरलैस क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा।
- 3जी और ब्रॉडब्रैण्ड वायरलैस अभिगम स्पेक्ट्रम प्रभारों के लिए भुगतान।
- मोबाइल वायरलैस क्षेत्र में प्रति प्रयोक्ता औसत राजस्व (एआरपीयू) में कमी।

व्यय में वृद्धि का प्रमुख कारण इसका विरासत में प्राप्त बड़ा कार्यबल है जिसके परिणामस्वरूप बीएसएनएल के कर्मचारियों के लिए होने वाला खर्च राजस्व का लगभग 50% है और एमटीएनएल के लिए यह खर्च 103% है।

(ग) और (घ): सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के पुनरूजीवन और पुनरूद्धार के लिए अल्पावधिक, मध्यावधिक और दीर्घावधिक उपायों का सुझाव देने के लिए दिनांक 17.04.2013 को मंत्री समूह (जीओएम) का गठन किया था। मंत्री समूह की बैठक दिनांक 12.06.2013, 01.08.2013 और 12.09.2013 को आयोजित की गई। मंत्री समूह द्वारा की गई सिफारिशें निम्न प्रकार से हैं:-

(i) बीएसएनएल के समान ही एमटीएनएल के कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान।

(ii) बीएसएनएल द्वारा छः लाइसेंस सेवा क्षेत्रों और एमटीएनएल द्वारा दो सेवा क्षेत्रों (दिल्ली एवं मुंबई) में ब्राडबैण्ड वायरलैस अभिगम स्पेक्ट्रम का अभ्यपर्ण और इस स्पेक्ट्रम के लिए बीएसएनएल द्वारा चुकाई गई राशि को वापस किया जाना।

(iii) बीएसएनएल के गठन के समय इसकी पूंजी संरचना के भाग के रूप में भारत संचार निगम लिमिटेड को दिए 7500 करोड़ रूपए के राष्ट्रीय ऋण के ब्याज सहित अदत हिस्से की माफी।

मंत्री समूह की उपर्युक्त सिफारिशें मंत्रिमण्डल के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जा रही हैं।

******